## Important News: India

### 1. वानिकी पहलों के माध्यम से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

**चर्चा में क्यों?**

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संयुक्त रूप से **वानिकी संबंधी पहलों के माध्यम से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)** जारी की।

**प्रमुख बिंदु**

- झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी इन 13 नदियों के लिए DPR जारी किए गए हैं।
- DPR को राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड (MoEF&CC) द्वारा वित्तपोषित किया गया और इसे भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) देहरादून, द्वारा तैयार किया गया।
- 13 नदियां सामूहिक रूप से 18,90,110 वर्ग किमी के कुल बेसिन क्षेत्र को आच्छादित करती हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 57.45 फीसदी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
- परियोजना के अंतर्गत 202 सहायक नदियों सहित 13 नदियों की लंबाई 42,830 किमी है।
- DPR रिवर फ्रंट, इको-पार्क विकसित कर और जनता के बीच जागरूकता लाकर संरक्षण, वनीकरण, जलग्रहण उपचार, पारिस्थितिक बहाली, नमी संरक्षण, आजीविका में सुधार, आय बढ़ाने, पारिस्थितिक पर्यटन पर केंद्रित है।
- 13 DPR का प्रस्तावित बजट 19,342.62 करोड़ रुपये है।
- यह ग्लासगो में नवंबर 2021 के दौरान CoP-26 में पंचामृत प्रतिबद्धता की दिशा में देश की प्रगति को मजबूत करेगा। इसके तहत भारत ने 2030 तक अपने अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को एक अरब टन कम करने, 2030 तक अक्षय ऊर्जा के साथ 50 प्रतिशत ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने, 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने, 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना है।

**नोट:** नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है।

**स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस**

## 2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप

### चर्चा में क्यों?

- भारत को एक प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के कार्य में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र के बीच एक मजबूत ढांचा और तालमेल विकसित करने हेतु पर्यटन मंत्रालय ने **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप** तैयार किया है।

Ministry of Tourism
Government of India

### प्रमुख बिंदु

- चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य को और आगे बढ़ाने में समर्पित संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने माननीय मंत्री (पर्यटन) की अध्यक्षता में एक **राष्ट्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन बोर्ड** का गठन किया है।
- पर्यटन मंत्रालय अपनी मौजूदा गतिविधियों के हिस्से के रूप में देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों व उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के तहत विदेशों में महत्वपूर्ण और संभावित बाजारों में वैश्विक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑनलाइन मीडिया अभियान संचालित करता है।
- 'मेडिकल वीजा' की शुरुआत की गई है, जो चिकित्सा उपचार के लिए भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों को विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया जा सकता है।
- 156 देशों में सुविधा के लिए 'ई-मेडिकल वीजा' और 'ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा' भी प्रारंभ किए गए हैं।
- पर्यटन मंत्रालय विभिन्न पहल के जरिये चिकित्सा/पर्यटन मेलों, चिकित्सा सम्मेलनों, स्वास्थ्य सम्मेलनों, स्वास्थ्य मेलों और संबद्ध रोड शो में भाग लेने के लिए अस्पतालों तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABH) द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा पर्यटन सेवा प्रदाताओं को बाजार विकास सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

### पर्यटन मंत्रालय की अन्य प्रमुख योजनाएं:

- स्वदेश दर्शन योजना
- प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल पहल
- देखो अपना देश अभियान
- प्रसाद योजना

**स्रोत: PIB**

## 3. UDAN योजना के तहत 405 हवाई अड्डे

### चर्चा में क्यों?

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI), कार्यान्वयन एजेंसी, ने 948 मार्गों को प्रदान किया है, जिसमें से 09.03.2022 तक उड़ान के तहत 8 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरोड्रोम सहित 65 हवाई अड्डों से जुड़े 405 मार्गों का संचालन किया गया है।

### प्रमुख बिंदु

### उड़ान योजना के बारे में:

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को प्रोत्साहित करने और हवाई यात्रा को आम जनता के लिए किफायती बनाने के लिए 21-10-2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) - उड़ान (उड़े देशका आम नागरिक) शुरू किया।
- एक हवाईअड्डा जो उड़ान के प्रदान किए गए मार्गों में शामिल है और RCS संचालन शुरू करने के लिए उन्नयन/विकास की आवश्यकता है, "अनारक्षित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों के पुनरुद्धार" योजना के तहत विकसित किया गया है।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI), कार्यान्वयन एजेंसी ने RCS उड़ानों के संचालन के लिए उड़ान के तहत अब तक 14 वाटर एयरोड्रोम और 36 हेलीपैड सहित 154 RCS हवाई अड्डों की पहचान की है।
- वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) के अलावा, केंद्र, राज्य सरकारों और हवाईअड्डा ऑपरेटरों से अन्य रियायतें चयनित एयरलाइन ऑपरेटरों (SAO) को प्रदान की जाती हैं ताकि असेवित/अयोग्य हवाई अड्डों/हेलीपोर्टों/वाटर एयरोड्रोम से संचालन को प्रोत्साहित किया जा सके और हवाई किराए को वहनीय रखा जा सके।

**स्रोत: PIB**

## 4. भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (IBPR) के रास्ते हल्दिया से जहाज पर माल लादने के बाद पांडु बंदरगाह पर ब्रह्मपुत्र लंगर पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज

### चर्चा में क्यों?

- बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने उस वक्त एक उपलब्धि हासिल की जब एमवी राम प्रसाद बिस्मिल ब्रह्मपुत्र पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया।
- केन्द्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग (PSW) और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हल्दिया में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से दो जहाजों - डीबी कल्पना चावला और डीबी एपीजे अब्दुल कलाम के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

### प्रमुख बिंदु

- 90 मीटर लंबा बेड़ा 26 मीटर चौड़ा और 2.1 मीटर गहरा है।
- इसके साथ ही इसने गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर लंगर डालने के बाद कोलकाता में हल्दिया गोदी से भारी माल ढुलाई के महत्वाकांक्षी परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया।
- इस प्रारंभिक कार्य का महत्व इसलिए है क्योंकि यह भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (IBPR) के रास्ते कोलकाता से गुवाहाटी तक माल लादने का कार्य शुरू करने के लिए मार्ग बताता है।
- भारत सरकार ने बांग्लादेश की सरकार के साथ इस खंड के तलकर्षण को - क्रमशः 80:20 अनुपात के साथ - निर्बाध नेविगेशन के लिए वित्त पोषित किया है।
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के साथ-साथ बांग्लादेश अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण (BIWTA) ने मिलकर काम किया ताकि यह ऐतिहासिक माल ढुलाई का कार्य सुचारू रूप से चल सके।

**नोट:** इससे पहले एमवी लाल बहादुर शास्त्री ने पटना से पांडु तक भारतीय खाद्य निगम (FCI) के लिए 200 मीट्रिक टन खाद्यान्न की एक खेप को गंगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (NW1) और ब्रह्मपुत्र राष्ट्रीय जलमार्ग 2 (NW2) के बीच माल की ढुलाई के परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया था।

**स्रोत: PIB**

## 5. उपभोक्ता मामले विभाग ने 'उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह' का जश्न शुरू किया

### चर्चा में क्यों?

- उपभोक्ता मामले विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रगतिशील भारत के 75 साल और यहां के लोगों, संस्कृति और उनकी उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने के लिए 14 मार्च, 2022 को "उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह" शुरू किया।

### प्रमुख बिंदु

- अपनी तरह की पहली पहल में, उपभोक्ता मामले विभाग के तहत आने वाले संगठनों की क्षेत्रीय इकाइयों यानी भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), भारतीय कानूनी मापिकी संस्थान (IILM) रांची, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF), नेशनल टेस्ट हाउस (NTH) और क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं (RRSL) ने आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के 85 से अधिक गांवों में उपभोक्ता जागरूकता और ग्राम पहुंच कार्यक्रम आयोजित किए।
- ग्राम पहुंच कार्यक्रमों के जरिए **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019**, भारतीय मानक चिह्नों, हॉलमार्क वाले आभूषण, CRS चिह्न की विशेषताओं और डिब्बाबंद वस्तुओं पर देखे जाने वाले विवरण, उचित वजन और माप के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा की और उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 14404 या 1800-11-4000 पर उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के बारे में जानकारी दी।

**स्रोत: न्यूज़ऑनएयर**

**Important News: State**

## 6. मुंबई शून्य उत्सर्जन रोडमैप विस्तार करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बना

**चर्चा में क्यों?**

- मुंबई की जलवायु कार्य योजना (MCAP) ने देश के 2070 के लक्ष्य से दो दशक पहले, 2050 तक पूर्ण कार्बन तटस्थता तक पहुंचने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जो ग्लासगो में COP -26 में प्रतिबद्ध था।

**प्रमुख बिंदु**

- योजना का उद्देश्य समावेशी और मजबूत शमन और अनुकूलन रणनीतियों को अपनाकर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए शहर के लिए 30 साल के रोड मैप के रूप में काम करना है।
- पिछले छह महीनों में ग्रीनहाउस गैस (GHG) और प्राकृतिक हरित आवरण सूची के भेद्यता मूल्यांकन के बाद, BMC ने विश्व संसाधन संस्थान (WRI), भारत और C40 शहरों के नेटवर्क से तकनीकी सहायता के साथ योजना तैयार की।
- MCAP छह क्षेत्रों पर केंद्रित है - ऊर्जा और भवन, सतत अपशिष्ट प्रबंधन, सतत गतिशीलता, शहरी हरित और जैव विविधता, वायु गुणवत्ता, शहरी बाढ़ और जल संसाधन प्रबंधन।
- योजना के अंतरिम और दीर्घकालिक उद्देश्यों में 2030 तक उत्सर्जन में 30 प्रतिशत की कमी, 2040 तक 44 प्रतिशत की कमी और आधार वर्ष उत्सर्जन (2019) की तुलना में 2050 तक शुद्ध-शून्य कमी शामिल है।

**स्रोत: ET**

## 7. देश का पहला डिजिटल वाटर बैंक 'एक्वेरियम' बेंगलुरु में लॉन्च हुआ

**चर्चा में क्यों?**

- देश का पहला डिजिटल वाटर बैंक **'एक्वेरियम'** बेंगलुरु में लॉन्च किया गया।

**प्रमुख बिंदु**

- यह पहल एक्वाक्राफ्ट वेंचर्स द्वारा की गई है, जो एक ऐसी कंपनी है जो सभी को पेयजल और स्वच्छता प्रदान करने के लिए स्थायी पहल में विशेषज्ञता रखती है।
- यह सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता के साथ टिकाऊ और हरित प्रौद्योगिकियों का संयोजन करने वाला एक बहुत ही अनूठा नवाचार है।
- डिजिटल वाटर डेटा बैंक को सभी संस्थानों और स्रोतों से 'जल डेटा' की एक क्यूरेटेड सूची के रूप में समझा जा सकता है जो कुछ सामान्य विकास चुनौतियों से निपटने में सहायता करेगा।

**स्रोत: न्यूज़ऑनएयर**

**Important News: Personality**

## 8. आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल कुमुदबेन जोशी का निधन

- आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कुमुदबेन मणिशंकर जोशी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- कुमुदबेन जोशी 26 नवंबर 1985 से 7 फरवरी 1990 तक आंध्र प्रदेश की राज्यपाल रहीं।
- वह शारदा मुखर्जी के बाद राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल थीं।
- जोशी तीन बार राज्यसभा की सदस्य रही।

**स्रोत: न्यूज़ऑनएयर**

## 9. 16 मार्च, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस

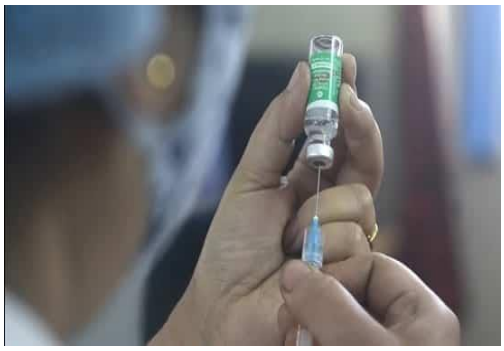

### चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है।

### प्रमुख बिंदु

- घातक बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित करने में हमारी मदद करने के लिए टीके आवश्यक हैं।
- राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का विषय 'वैक्सीन वर्क फॉर ऑल' है।

### इतिहास:

- यह 16 मार्च, 1995 को था, जब पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के चालू होने के बाद पहली बार आधिकारिक तौर पर इस दिन को मनाया गया था।
- ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक 1995 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल, जो 1988 में शुरू हुई थी, के तहत इसी तारीख को दी गई थी।
- हालाँकि, पोलियो के खिलाफ टीकाकरण 1978 में शुरू हो चुका था और 27 मार्च 2014 को WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था।